सम्पादक के नाम

आरबीआई के गवर्नर पद के लिए इतिहास के छात्र का चयन हुआ है, मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ इसलिए काफ़ी उत्साहित हूँ

अगर मैं स्टूडियो में एंकरिंग न कर रहा होता तो मेरा चांस था। सूत्रों को पता लग गया था कि मैं गणित में फिसड्डी भी हूँ।

पर तभी इतिहास के एक और छात्र का नाम किसी ने सरकार को सुझा दिया और मेरा पत्ता कट गया। शक्ति कांत दास जी को बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि वे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इतिहास के पहले छात्र होंगे।

वैसे एक वेकेंसी और है। अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अंशकालिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है। वे अब सीएनएन आईबीएन के सलाहकार बन गए गए हैं।पहले लोग न्यूज़ चैनल छोड़ कर प्रधानमंत्री का सलाहकार बनते थे लेकिन सुरजीत भल्ला ने ट्रेंड बदला है। जब मीडिया के लिए अर्थव्यवस्था को मैनेज करना है तो क्यों न मीडिया में ही जाकर अर्थव्यवस्था को मैनेज किया जाए। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने निजी कारणों से इस्तीफ़ा दिया है लेकिन मैं तो निजी कारणों से ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुंबई रहने का बहुत मन है। गवर्नर बनकर ये शौक़ पूरा हो जाता।

इसलिए भल्ला की जगह जो पद रिक्त हुआ है उसके लिए कोई चाहे तो मेरा नाम सुझा सकता है। तीन मूर्ति में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आर्थिक मामलों में दिलचस्पी रखता हूँ। फ़ेसबुक पर आर्थिक मामलों को लेकर कई सौ पोस्ट लिखे हैं। जिन्हें मूल रूप में दूसरों ने लिखा था। आज सही में मिस कर गया। टेम्पो में बैठा रह गया और बगल से बस निकल गई! हिन्दी में लिखा है ताकि लोग मेरी बातों की गंभीरता को व्यंग्य में लें।

- रवीश कुमार

राहुल को साबित करना होगा कि यह बदली हुई कांग्रेस है वरना उम्मीद की कोई वजह नहीं

हिमांशु कुमार

तीन राज्यों में भाजपा हारी है और कांग्रेस जीती है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा आशंकित हूं। मेरी आशंका के क्या कारण हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा।

मेरा कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ का बस्तर रहा है। पिछले कुछ समय से मेरे लेखों में भाजपा के समय हुए अत्याचारों की रिपोर्टें प्रकशित होती रही हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब दिल्ली में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और पी. चिदंबरम गृहमंत्री थे, मेरी बहुत सारी रिपोर्टें कांग्रेस की सरकारों के ज़ुल्मों और गैरकानूनी कामों के खिलाफ लिखी गई थीं।

जब हम छत्तीसगढ़ में थे उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेता जो विपक्षी दल का नेता महेंद्र कर्मा था, वह गैरकानूनी अभियान सलवा जुडूम का नेतृत्व कर रहा था। सलवा जुडूम को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान विरोधी घोषित किया। कांग्रेस ने आज तक सलवा जुडूम के दौरान किये गये ज़ुल्मों के लिए माफी नहीं मांगी है।

मुझे अच्छे से याद है जब सारकेगुडा में सीआरपीएफ ने माटी त्योहार मना रहे सत्रह आदिवासियों को गोलियों से भून डाला था जिनमें नौ बच्चे बच्चियां भी थीं, तब कांग्रेस के गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने पूरी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के इस भयानक काम की तारीफ़ की थी और प्रेस कांफ्रेंस कर के कहा था कि हमारे सुरक्षा बलों ने दुर्दांत माओवादियों को मार डाला है जबकि दंतेवाड़ा ज़िले के कांग्रेस के बनाये गये जांच दल ने माना था कि सुरक्षा बलों ने निर्दोष आदिवासियों की हत्या की है।

मैं खुद भी जब चिदंबरम से मिला था तो उन्होंने मेरे मुंह पर रमन सिंह की बड़ी तारीफें की थीं। आज किस मुंह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, भाजपा के कामों का विरोध कर रही है जब खुद उसने केंद्र में रहते हुए बड़े कार्पोरेट के लिए ज़मीनें छीनने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को मदद दी और उसका समर्थन किया था ?

अगर आप इसलिए खुश हैं कि अब कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में आ गया है इसलिए अब कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रह गई है, तो कांग्रेस को यह साबित करना होगा। कांग्रेस पहले सलवा जुडूम के लिए माफी मांगे। कांग्रेस पहले भाजपा सरकार द्वारा सोनी सोरी पर लगाये गये फर्ज़ी केस वापस ले और सोनी सोरी के गुप्तांगों में पत्थर भरने वाले पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज़ करने का आदेश दे और उसे जेल में डाले। सोनी सोरी द्वारा उठाये गए मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच शुरू करवाए।

कांग्रेस में साहस है तो सुकमा के कलेक्टर अलेक्स पाल मेनन के नक्सलियों द्वारा अपहरण के बाद जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने के लिए बनाई गई बुच समिति को जीवित करे और निर्दोष आदिवासियों को जेलों से रिहा होने में अड़चन न पैदा करे।

मुझे याद है जब सुकमा जिले के गोमपाड गांव में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने सोलह आदिवासियों को तलवारों से काट दिया था जिसमें अस्सी साल की महिला के स्तन काट डाले थे और डेढ़ साल के बच्चे का हाथ काट दिया था। जब इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट आया तो कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ कोर्ट में अपने वकील खड़े किये और मुझे नक्सली कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुझे नक्सली समर्थक कहने पर डांट पिलाई थी। आज भी वह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है।

मैं यह भी नहीं भूल सकता कि कांग्रेस के समय में ही भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने मेरे सुप्रीम कोर्ट में मामले उठाने पर बयान दिया था कि अब माओवादी अदालतों की मदद ले रहे हैं और मैंने जवाब में लिखा था कि आपको तो खुश होना चाहिए कि माओवादी कानून और संविधान को मान रहे हैं और अगर कोर्ट में जाना भी माओवाद है तो हमें लिस्ट देकर बता दीजिये कि आपकी नज़र में और क्या क्या माओवाद होता है?

कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में इस्लामी आतंकवाद का हौव्वा कांग्रेस के समय में ही खड़ा किया गया था। टाडा, पोटा, मकोका, यूएपीए जैसे दमनकारी कानून कांग्रेस के ही समय में लाये गये थे और इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किये गये लोगों में नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा लोग मुसलमान थे जो बाद में निर्दोष घोषित किये गये।

कांग्रेस के समय में भारत के गृह मंत्रालय ने इंडियन मुजाहिदीन जैसे काल्पनिक आतंकवादी संगठन का हौव्वा खड़ा किया और भारत की आईबी के लोगों ने मुस्लिम आतंकवाद का हौव्वा सही साबित करने के लिए अपने एजेंटों के द्वारा मुसलमान लड़कों को भड़का कर उन्हें उग्र बनाने की हरकतें कीं, जिनका खुलासा रिहाई मंच कई मामलों में अपनी जांच रिपोर्टों में कर चुका है। कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था और देश में साम्प्रदायिक राजनीति का रास्ता साफ़ किया था।

कांग्रेस के समय में छत्तीसगढ़ में नगरनार लोहा कारखाने के लिए जब ज़मीन ली गई थी तब पूरे गांववालों को जेल में डाल दिया गया था जिनमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और बस्तर की कलेक्टर ऋचा शर्मा द्वारा ग्राम सभा के रजिस्टर में से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पारित ग्राम सभा के प्रस्ताव को फाड़ कर खुद फर्जी ग्राम सभा की कार्यवाही लिखी गई थी और नगरनार की ज़मीन ले ली गई थी।

हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी को समझाएं कि आप मन्दिर में गए, जनेऊ पहना इसलिए जीत गये। ऐसे में कांग्रेस अपनी बर्बादी खुद ही तय कर लेगी। जो जनता राम, गाय और मन्दिर के झांसे में नहीं आई वह जनेऊ और राहुल के गोत्र और शिव पूजा के झांसे में भी नहीं आने वाली।

कांग्रेस अगर अपने को अब बदला हुआ, सुधरा हुआ और अब अच्छी बन चुकी पार्टी साबित करना चाहती है तो उसे यह अपने कामों से साबित करके दिखाना होगा।

छत्तीसगढ़ में हमने जिन आदिवासियों के ऊपर हुए ज़ुल्मों- जिनमें आदिवासियों के घर जलाने, उनकी महिलाओं से बलात्कार करने, उनके बच्चों की हत्याएं करने- के मामलों के खिलाफ अदालत जाकर न्याय मांगने में मदद की, उन मुकदमों में बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी फंसे हुए हैं।

इसके अलावा सलवा जुडूम के नए संस्करणों में कांग्रेसी गुंडे बराबर शामिल रहे हैं। अब ये कांग्रेसी नेता पुलिस के साथ मिलकर हमारे ऊपर वैसे ही हमले करेंगे जैसे भाजपाई करते थे। आज सुबह सोनी सोरी से मेरी बात हुई है। सरकार बदलने से कुछ बदलने की उम्मीद हम नहीं कर रहे।

जनादेश ने लोकतंत्र के चौराहे पर ला खड़ा किया साहेब को

पुण्य प्रसून बाजपेयी

आसान है कहना कि 2014 में उगा सितारा 2019 में डूब जायेगा। ये भी कहना आसान है पहली बार किसान-मजदूर-बेरोजगारी के मुद्दे सतह पर आये तो शहरी चकाचौंध तले विकास का रंग फीका पड़ गया। ये कहना भी आसान है कि बीजेपी आंकड़ों के लिहाज से चाहे विस्तार पाती रही लेकिन अपने ही दायरे में इतनी सिमटी मोदी-शाह-जेटली से आगे देख नहीं पायी। और ये भी कहना आसान है कि साल भर पहले कांग्रेस की कमान संभालने वाले राहुल गांधी ने पप्पू से राहुल के सफर को जिस परिपक्वता के साथ पूरा किया उसमें काग्रेस के दिन बहुरने दिखायी देने लग गये। लेकिन सबसे मुश्किल है अब ये समझना कि जिस लोकतंत्र की धज्जियां दिल्ली में उड़ायी गई उसके छांव तले राजस्थान, छत्तिसगढ और मध्यप्रेदश कैसे आ गये। और अब क्या 2019 के फेर में लोकतंत्र और ज्यादा लहूलुहान होगा। क्योंकि जहां जहां दांव पर दिल्ली थी वहा वहा सबसे बुरी हार बीजेपी की हुई।

छत्तीसगढ़ में अडानी के प्रोजेक्ट हैं तो रुपया पानी की तरह बहाया गया । पर जनादेश की आंधी ऐसी चली कि तीन बार की रमन सरकार ही बह गई। मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल सरीखे शहरी इलाकों में भी बीजेपी को जनता के मात दे दी। जहां की सीट और कोई नहीं अमित शाह ही तय कर रहे थे । और राजस्थान में जहां जहां वसुंधरा को धूल चटाने के लिये मोदी – शाह की जोड़ी गई वहा वहा वसुंधरा ने किला बचाया और जिन 42 सीटों को दिल्ली में बैठ कर अमित शाह ने तय किया उसमें से 34 सीटों पर बीजेपी की हार हो गई । तो क्या वाकई 2014 की जीत के नशे में 2019 की जीत तय करने के लिये बीजेपी के तीन मुख्यमंत्रियो का बलिदान हुआ। या फिर कांग्रेस ने वाकई पसीना बहाया और जमीनी स्तर पर जुडे कार्यकत्ताओं को महत्ता देकर अपने आलाकमान के पिरामिड को इस बार पलट दिया । यानी ना तो पैराशूट उम्मीदवार और ना ही बंद कमरो के निर्णयों को महत्व ।

तो क्या बूथ दर बूथ और पन्ने दर पन्ने की सोच तले पन्ना प्रमुख की रणनीति जो शाह बनाते रहे वह इस

बार टूट गयी । हो सकता है ये सारे आंकलन अब शुरु हो लेकिन महज चार महीने बाद ही देश को जिस आमचुनाव के समर में कूदना है उसकी बिसात कैसी होगी और इन तीन राज्यों में काग्रेस की जीत या बीजेपी के हार कौन सा नया समीकरण तैयार कर देगी अब नजरे तो इसी पर हर किसी की होगी। हां, तेलगाना में काग्रेस की हार से ज्यादा चन्द्रबाबू के बेअसर होने ने उस लकीर को चाहे अनचाहे मजबूत कर दिया कि कि अब गठंबधन की शर्ते क्षत्रप नहीं काग्रेस तय करेगी। यानी जनादेश ने पांच सवालो को जन्म दे दिया है ।

पहला , अब मोदी को चेहरा बनाकर प्रेजीडेन्शिल फार्मेट की सोच की खुमारी बीजेपी से उतर जायेगी। दूसरा, मोदी ठीक है पर विकल्प कोई नहीं की खाली जगह पर ठसक के साथ राहुल गांधी नजर आयेगें । तीसरा , दलित वोट बैक की एकमात्र नेत्री मायावती नहीं है और 2019 में मायावती के सौदेबाजी का दायरा बेहद सिमट गया।

चौथा, महागठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी को खारिज करने की स्थिति में कोई नहीं होगा । पांचवा, बीजेपी के सहयोगी छिटकेंगें और शिवसेना की सौदेबादी का दायरा ना सिर्फ बीजेपी को मुश्किल में डालेगा बल्कि शिवसेना मोदी पर सीधा हमला बोलेगी । तो क्या वाकई काग्रेस के लिये अच्छे दिनों की आहट और बीजेपी के बुरे दिन की शुरूआत हो गई । अगर इस सोच को भी सही मान लें तो भी कुछ सवालो का जवाब जो जनता जनादेश के जरिये दे चुकी है उसे जुबां कौन सी सत्ता दे पायेगी ये अपने आप में सवाल है। मसलन राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों सत्ता कांग्रेस को मिल रही है । यानी सत्ता पर कर्ज है । तीन राज्यों में किसान-मजदूर-युवा बेरोजगार बेहाल हैं। तीनों राज्यो में उघौगिक विकास ठप पडा है । तीनो राज्यो में खनिज संसाधनो की लूट चरम पर है । मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ में तो संघ के स्वंयसेवकों की टोलियों का कब्जा सरकारी संस्थानो से लेकर सिस्टम के हर पुर्जे पर है। और सबसे बडी बात तो ये है कि मोजूदा दौर में जो खटास राजनीतिक तौर पर उभरी वह सिर्फ बयानबाजी या राजनीतिक हमले भर की नहीं रही ।

बल्कि सीबीआई और इनकमटेक्स के अधिकारियो ने कांग्रेसी पर मामला भी दर्ज किया और छापे भी मारे । कांग्रेस को फाइनेन्स करने वाले छत्तीसगढ के 27 और मध्यप्रदेश के 36 लोगों पर दिल्ली से सीबीआई और इनकमटैक्स के छापे पड़े। यानी राजनीतिक तौर तरीके पारंपरिक चेहरे वाले रहे नहीं हैं । तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन राज्य में जिस तल्खी के साथ उभरेगें उसमें इस बात का इंतजार करना होगा कि अब कांग्रेस के लिये संघ का मतलब सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भर नहीं होगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती क्योकि मोदी भी समझ रहे है और राहुल गांधी भी जान रहे है कि अगले तीन महीने की सत्ता 2019 की बिसात को तय करेगी । यानी सत्ता चलाने के तौर तरीके बेहद मायने रखेगें। खासकर आर्थिक हालात और सिस्टम का काम करना । मोदी के सामने अंतरिम बजट सबसे बडी चुनौती है। तो काग्रेस के सामने नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र को पटरी पर लाने और ग्रामीणों के हालत में सुधार तत्काल लाने की चुनौती है । और संयोग से इनकी तादाद सबसे ज्यादा उन्ही तीन राज्यों में है जहां काग्रेस को जीत मिली है ।

फिर भ्रष्टचार के मुद्दों को उठाकर 2014 में जिस तरह बार बार मोदी ने कांग्रेस को घेरा अब इन्ही तीन राज्यो में भ्रष्टचार के मुद्दो के आसरे कांग्रेस बिना देर किये बीजेपी को घेरेगी । मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो या वसुंधरा का ललित मोदी के साथ मिलकर खेल करना या फिर रमन सिंह का पनामा पेपर । और इस रास्ते को सटीक तरह से चलाने के लिये तीनों राज्यों में जो तीन चेहरे कांग्रेस सबसे फिट है उसमें मध्यप्रदेश में कमलनाथ । तो राजस्थान में सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही फिट बैठते है । और ये तिगड़ी कांग्रेसी ओल्ड गार्ड और युवा को भी बैलेंस करती है । और बघेल के जरीये रमन सिंह या छत्तीसगढ़ में अडानी के प्रोजक्ट पर भी लगाम लगाने की ताकत रखती है । पर इस कड़ी में आखिरी सवाल यही है कि अब शिवराज, रमन सिंह और वसुंधरा का क्या होगा । या फिर मोदी – शाह की जोड़ी अब कौन सी बिसात बिछायेगी या फिर मोदी सत्ता कौन सा तुरुप का पत्ता देश के सामने फेंकेगीं ।

या फिर बीजोपी के भीतर से वाकई कोई अवाज उठेगी या संघ परिवार जागेगा। लेकिन ध्यान दें तो कोई विकल्प अब बीजेपी के भीतर नहीं है । मोदी के बाद दूसरी कतार के नेता ऐसे हैं जो अपना चुनाव नहीं जीत सकते है या फिर उनकी कोई पहचान किसी राज्य तो दूर किसी लोकसभा सीट तक की नहीं है । मसलन, अरुण जेटली , धर्मेन्द्र प्रधान , पियूष गोयल या निर्मला सीतारमण । और इस कड़ी में हारे हुये मुख्यमंत्रियो को अमित शाह कौन सी जगह देंगें ये भी सवाल है । यानी जनादेश ने साफ तौर पर बतलाया है कि जादू या जुमले से देश चलता नहीं और मंदिर नहीं सवाल पेट का होगा । शायद इसीलिये पांच राज्यों के जनादेश ने मोदी को लोकतंत्र के चौराहे पर ला खड़ा किया है ।